



॥ श्री ॥

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

निग - 1768-PB&-16

श्री आदोष बैद्य अमित
द्वारा उज्जैन के पर

31-5-16 के अनुत्ता
31-5-16

मदनलाल पिता मांगियाजी जाति बागरी
निवासी ग्राम भौमलवास तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म.प्र.

.....आवेदक
विरुद्ध

सुरेश पिता परमेश्वरजी जाति माली
निवासी ग्राम पिपलू तहसील बड़नगर
जिला उज्जैन म.प्र.

.....अनावेदक

निगरानी धारा 50 भू.रा.सं.

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी
बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक
69 / अप्रैल / 11-12 आदेश दिनांक
29 / 03 / 2016 के विरुद्ध निगरानी ।

~~अधिकारी
द्वारा दिए गए
उत्तराधिकारी~~

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है-

01 यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने नामांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील की कार्यवाही धारा 32 भू.रा.सं. के आवेदन के आधार पर सिविल वाद के अंतिम निराकरण तक स्थगित करने मे वैधानिक त्रुटी की है। सिविल वाद मे आवेदक के पक्ष मे आधिपत्य बाबद अनावेदक के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गई। अपील प्रकरण के विचारण सम्बंधी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो इस संहिता द्वारा उसमे निहित न की गई हो तथा अपनी अधिकारिता का अविधिपूर्ण सारवान अनियमितता के साथ प्रयोग किया है।

02 यह कि आवेदक द्वारा अरबअली पिता नगजी नायता निवासी पलदूना से 9.000/- रुपये कर्ज प्राप्त किये थे। अरबअली ने आवेदक की निरक्षरता का लाभ उठाकर आवेदक की भूमी सर्वे नंबर 368 रकबा 2.37 का मखत्यारनामा अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया, जिसकी आवेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुबृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1768-पीबीआर/16

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५-२०१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष वैध उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २०-३-१९ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3) </p> <p></p> <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	